संख्या-259/2025/2268/22-2-2024-17(01)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुगरा पत्नी श्री लाला, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-38867/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.12.2024) दिनांक 20.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुगरा पत्नी श्री लाला, वार्ड नं0-10, कस्वा सखानू, थाना-अलापुर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। दहेज की माँग को लेकर दिनांक 14.08.2010 को महिला बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी बहू जाहिरा खातून की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-98/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-06, बदायूँ के आदेश दिनांक 14.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2019 द्वारा महिला बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 20.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 01 माह 25 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी। उक्त आख्या में महिला बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की माँग को लेकर दिनांक 14.08.2010 को महिला बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी बहू जाहिरा खातून की आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ज्ञान प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बंदी सुगरा पत्नी श्री लाला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुगरा (बंदी संख्या-572/2022) पत्नी श्री लाला, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-259/2025/2268(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-259/2025/2268/22-2-2024-17(01)/2025

दिनांक 12 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुगरा पत्नी श्री लाला, वार्ड नं0-10, कस्वा सखानू, थाना-अलापुर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। दहेज की माँग को लेकर दिनांक 14.08.2010 को महिला बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी बहू जाहिरा खातून की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-98/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-06, बदायूँ के आदेश दिनांक 14.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2019 द्वारा महिला बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 20.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 01 माह 25 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी। उक्त आख्या में महिला बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की माँग को लेकर दिनांक 14.08.2010 को महिला बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी बहू जाहिरा खातून की आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ज्ञान प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बंदी सुगरा पत्नी श्री लाला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।